दो मामलों में डीलर द्वारा गणना में की गई गलती के कारण 8 सप्ताह से अधिक की देरी हुई (एक वाहन की सुपुर्दगी अभी की जानी है।)

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, डीलर बुकिंग के समय आर्डर बुकिंग फार्म भर कर ग्राहक को दे देता है। इस फार्म में सुपुर्दगी की अनुमानित: अवधि अंकित की जाती है। ग्राहकों को वाहनों की सुपुर्दगी भुगतान की वरीयता के अनुसार ही की जाती है। मारुति उद्योग लिमिटेड के फील्ड कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहनों की सुपुर्दगी भुगतानों की वरीयता के अनुसार की जा रही है, डीलरों के कार्य का आवधिक निरीक्षण करते है। कभी-कभी किसी विशेष रंग का वाहन उपलब्ध न होने अथवा वाहनों की हड़ताल इत्यादि से प्रेषण/उत्पादन में बाधा पड़ने के कारण सुपुर्दगी में देरी होने की संभावना रहती है।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स की इकाई–वार स्थिति

2032. **श्री गया सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1993-94 में गत छः माह की अवधि के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों की स्थिति क्या थी और तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इकाइयों का अप्रैल-सितम्बर, 1993 तक का कार्य-निष्पादन (गैर लेखा-परीक्षित) नीचे दर्शाया गया है :–

(करोड़ रुपये)

इकाइयां/प्रभाग	कारोबार		कर पूर्व लाभ (वास्तविक)
	लक्ष्य	वास्तविक	
1	2	3	4
हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, भोपाल	295	259	12.33
ट्रांसफार्मर प्लांट, झांसी	96	52	4.13
हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार	141	51	−12.07
सेन्ट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट हरिद्वार	27	27	−2.28
हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद	229	210	22.87
हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, त्रिची	219	245	10.22
सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट, त्रिची	33	31	−2.12
बॉयलर एक्सलीयरीज प्लांट, रानीपेट	49	45	−4.42
इलेक्ट्रोनिक्स डिविजन बंगलौर	105	43	−5.93
इलेक्ट्रो पोर्सलेन डिविजन, बंगलौर	18	18	0.17
इन्सुलेटर प्लांट; जगदीशपुर	6	5	−4.10
इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट, गोइन्दवाल	3	2	−0.06
कम्पोनेंट फैब्रीकेशन प्लांट, रुद्रपुर	4	1	−0.37
इंडस्ट्रियल सिस्टम ग्रुप, बंगलौर	15	8	−1.48
पावर ग्रुप एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट्स	145	163	29.01
रिपेयर शॉप, वाराणसी	5	4	0.09
ट्रांसमिशन ग्रुप	7	7	−0.50
योग :	1,396	1,171	46.29

1	2	3	4
घटा अंतर विभागीय आपूर्तियां :	104	82	
शेष निवल	1292	1089 (लक्ष्य का 84 प्रतिशत)	
कर पूर्व लाभ		46	

Project in Konkan Region

2033. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the PRIME SBNIStteR be pleased to state:

(a) the number of projects proposed to be set up in Konkan Region of Maharashtra; and

(b) the steps taken by Government to streamline and accelerate the process of early setting up of industries especially in the backward regions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Region-wise information on Industrial approvals of a State is not centrally maintained. However, under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 72 Letters of Intent have been granted during 1992 and 1993 (Upto November) for setting up of industries in Thane, Raigad, Sindhudurg and Ratnagiri, districts which, *inter-atta,* constitute the Konkan Region.

Apart from these, 766 Industrial Entrepreneurs Memorandum have been filed during 1992 and 1993 (Upto November) for setting up of industries pertaining to delicensed sector in the said districts.

(b) Industrial development of a particular area is the primary responsibility of the State Government, while Government of India lays down the Industrial Policy. For development of backward areas, a Centrally Sponsored Scheme of growth centres has been adopted by the Government of India.

Restriction in payment of Bomus in Public Sector

2034. SHRI GURJJAS DAS GUPTA: Will the PRIME MINISTER he pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Public Enterprises (DPE) has issued a circular recently restricting payment of bonus/exgratia in the public sector;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Central Trade Unions have demanded the scrapping of this ogder; and

(d) if so, what is Government's feaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) Copy of the Circular is enclosed as statement *(See* below).

(c) and (d) No formal demand has been received from the Central Trade Unions by this Department so far for scrapping of these orders. However, the Ministry of Labour is examining a proposal for amending the provisions of the Payment of Bonus Act.